RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 23 JUNE TO 29 JUNE 2021 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 06 ■ अंक 44 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

महंगाईः पेट्रोल-डीजल की कीमतों से जनता परेशान Page 2

युवाओं के उत्साह से इंदौर ने रचा एक ही दिन में 2.25 लाख टीके लगाने का कीर्तिमान Page 3

क्या है कोरोना का नया डेल्टा + वैरिएंट क्यों माना जा रहा इसे संभावित तीसरी लहर की वजह? Page 7

editoria!

मेडिकल खर्च की मार

मेडिकल खर्च के कारण देश में पहले भी लोग गरीबी की भेंट चढ़ते रहे हैं, लेकिन कोरोना ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। 2012 के आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, जिनमें से 5.5 करोड़ अधिक मेडिकल खर्च की वजह से इस दलदल में फंस गए थे। इसकी वजह यह है कि यहां जब कोई बीमार होता है तो उसे इलाज में अपनी जेब से बहुत अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है। विश्व बैंक के मुताबिक, भारत में अगर किसी के इलाज पर 100 रुपये का खर्च आता है तो उसमें से 63 रुपये उसे अपनी जेब से देने पड़ते हैं। वहीं हमारे पड़ोस भूटान, श्रीलंका और पाकिस्तान में यह खर्च भारत की तुलना में कम है। चीन में भी यह हर 100 रुपये में 30 रुपये के करीब है। अमीर देशों की तो हालत कहीं अच्छी है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी में मरीजों को इलाज पर हर 100 रुपये में 20 रुपये से कम खर्च करना पड़ता है तो फ्रांस में यह 9 रुपये के करीब है। बाकी का पैसा सरकार खर्च करती है। भारत में राज्यों की बात करें तो वहां भी जहां गरीबी अधिक है, वहीं के लोगों को इलाज पर जेब से अधिक पैसा खर्च करना पड़ रहा है। बिहार में यह खर्च 99.90 रुपये है। इसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ओडिशा के लोगों को इलाज की खातिर अपनी जेब से काफी अधिक पैसा खर्च करना पड़ रहा है। इस वजह से देश में अधिक से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे धकेले जा रहे हैं। 1994 से 2014 के बीच नैशनल सैंपल सर्वे डेटा के आधार पर 2018 में एक स्टडी हुई। इसमें दावा किया गया कि 1993-94 में 3.9 फीसदी आबादी के सालाना खर्च में मेडिकल बिल का योगदान 25 फीसदी था। 2011-12 में ऐसे परिवारों की संख्या बढ़कर 4.3 फीसदी हो गई। इस स्टडी में कहा गया था कि इलाज पर खर्च की वजह से देश की करीब 4.5 फीसदी आबादी गरीबी की दलदल में फंस गई। कोरोना महामारी के दौर में रिटायरमेंट फंड से पैसा निकालने की खबरें भी सुर्खियां बनी हैं। छंटनी, वेतन में कटौती के साथ मेडिकल खर्च भी इसकी एक वजह रही है। दूसरे, भारत में सोशल सिक्योरिटी बहुत कमजोर है, इसलिए इलाज जैसे आकस्मिक खर्च से लोगों पर वित्तीय दबाव बढ़ जाता है। इसलिए यह जरूरी है कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च बढ़ाए। इस साल के आर्थिक सर्वे में भी कहा गया था, 'किसी देश की सेहत नागरिकों के समान, किफायती और जवाबदेह चिकित्सा तंत्र पर काफी हद तक निर्भर करती है।' सर्वे में स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च जीडीपी के 1 फीसदी से बढ़ाकर 2.5-3 फीसदी करने का सुझाव दिया गया था। इसमें कहा गया था कि स्वास्थ्य पर खर्च में इतनी बढ़ोतरी की जाए तो नागरिकों को हर 100 रुपये के खर्च में अपनी जेब से 30 रुपये ही देने पड़ेंगे। स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाने की मांग लंबे समय से होती रही है और महामारी के दौर में देश ने जो भुगता है, उसका संदेश यही है कि इसमें देर नहीं करनी चाहिए। यह सिर्फ नागरिकों की नहीं, देश की सेहत का सवाल है।

एक करोड़ जीएसटी देने वाले होटल कारोबारियों को मिलेगा 60 लाख ऋण

नई दिल्ली। एजेंसी

वर्किंग कैपिटल पर ऋण लेने वाले होटल कारोबारियों, ट्रेवल एजेंटों और रेस्टोरेंट संचालकों को कम ब्याज पर ऋण देने की योजना अधिसूचित हो गई है। एक करोड़ रुपये जीएसटी देने वाले होटल कारोबारियों को 60 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। एक से तीन करोड़ तक जीएसटी देने वालों को 90 लाख और तीन करोड़ से अधिक जीएसटी देने वाले होटल कारोबारियों को 1.20 करोड़ का ऋण मिल सकेगा। इसके अलावा जीएसटी जमा करवाने वाले रेस्टोरेंट संचालकों को बीस लाख और ट्रेवल एजेंटों को 15 लाख रुपये का ऋण दिया जाएगा। मंगलवार को पर्यटन विभाग ने कम ब्याज पर ऋण देने वाली योजना को संशोधित कर राजपत्र में अधिसूचित कर दिया है।

वर्किंग कैपिटल पर ऋण लेने वाले होटल कारोबारियों को अब पहले वर्ष में ब्याज में 75 फीसदी की छूट दी जाएगी। आर्थिक संकट से जूझ रहे प्रदेश के होटल कारोबारियों को सरकार ने बीते वर्ष 11 फीसदी ब्याज पर चार साल के लिए ऋण देने की योजना चलाई थी। ऋण की अवधि चार वर्षों के लिए रखी गई थी। इसमें पहले दो वर्षों तक ब्याज में हर वर्ष 50 फीसदी छूट दी जा रही थी। पहले दो वर्ष प्रदेश सरकार 50 फीसदी ब्याज चुका रही थी। इस योजना में अब संशोधन कर दिया गया है। अब ऋण की अवधि पांच साल कर दी गई है। इसके अलावा पहले वर्ष में 75 फीसदी तक ब्याज में छूट देने का फैसला लिया गया है। बीते दिनों हुई मंत्रिमंडल की बैठक में योजना को संशोधित किया गया है। संशोधित योजना की अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग के साथ सभी पंजीकृत इकाइयां ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

पर्यटन इकाई को किसी भी एजेंसी द्वारा पहले चूककर्ता/दिवालिया/ब्लैक लिस्टेड आदि नहीं होना चाहिए। ट्रवल एजेंटों को भी योजना के तहत कवर किया जाएगा। ऋण की अवधि पांच वर्ष होगी। ऋण सुविधा अधिस्थगन के पहले वर्ष के दौरान नकद ऋण के रूप में और शेष 4 वर्षों में इसे सावधि ऋण में परिवर्तित किया जाएगा। ऋण 48 ईएमआई में चुकाया जाएगा। एक वर्ष के अधिस्थगन के दौरान अनुदान 75 फीसदी होगा। ऋण की मुद्रा के दूसरे वर्ष पर ब्याज अनुदान 50 फीसदी होगा। शेष अवधि ब्याज सबवेंशन के बिना होगी। राज्य सहकारी बैंक, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक, जोगिंद्रा सहकारी बैंक और व्यावसायिक बैंकों के माध्यम से ऋण दिए जाएंगे।

OIL का मुनाफा चौथी तिमाही में 8% गिरा, कच्चे तेल का कम उत्पादन वजह

नई दिल्ली। एजेंसी

देश में दूसरे सबसे तेल निर्यातक ऑयल इंडिया लिमिटेड ने बताया कि मार्च तिमाही में नेट प्रॉफिट में 8 फीसदी की गिरावट आई है। इसकी वजह उसने कच्चे तेल के कम उत्पादन को बताया है। कंपनी ने बयान में बताया कि जनवरी-मार्च 2021 में उसका नेट प्रॉफिट 847.56 करोड़ रुपये या 7.82 रुपये प्रति शेयर रहा, जो पिछले साल की समान अवधि में 925.65 करोड़ रुपये या 8.54 रुपये प्रति शेयर का था।

तेल का उत्पादन 5.28% गिरा

कंपनी को तिमाही में कच्चे तेल के हर बैरल के लिए 59.80 अमेरिकी डॉलर मिले. एक साल पहले के 5.18 अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इसमें बढ़ोतरी है. लेकिन तेल का उत्पादन जनवरी-मार्च 2021 में 5.28 फीसदी गिरकर 0.72 मिलियन टन पर पहुंच गया। गैस आउटपुट 0.649 बिलियन क्यूबिक मीटर पर लगभग फ्लैट रहा. वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में टर्नओवर बढ़कर 3,909.61 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले 3,583.72 रुपये पर था। तेल की कम कीमतों के कारण 2020-21 में नेट प्रॉफिट गिरकर 1,741.59 करोड़ रुपये पर आ गया, जो पिछले वित्त वर्ष में 2,584.06 करोड़ रुपये था। 2020-21 में कच्चे तेल का उत्पादन 2.964 मिलियन टन रहा। यह 2019-20 के दौरान हुए 3.134 मिलियन टन उत्पादन के मुकाबले 5.42 फीसदी कम था। प्राकृतिक गैस का भी उत्पादन 2020-21 में 5.68 फीसदी घटकर 2642 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर रहा। OIL ने कहा कि उसके बोर्ड ने 2020-21 के लिए 1.50 रुपये प्रति शेयर के अंतिम डिविडेंड का सुझाव दिया था। इससे पहले कंपनी ने फरवरी में 3.50 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का भुगतान किया था। बयान में कहा गया है कि कंपनी ने 26 मार्च 2021 को नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (NRL) में अतिरिक्त 54.16 फीसदी ऑनरशिप इंट्रस्ट का अधिग्रहण किया है। NRL में इक्विटी हिस्सेदारी को बढ़ाकर 80.16 फीसदी की गई है, जिसमें असम सरकार की ओर से लिए गए 10.53 फीसदी शेयर शामिल हैं. अब NRL OIL की सब्सिडरी है।

कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का रुझान जारी

मुंबई। एजेंसी

कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का रुझान बना हुआ है। ब्रेंट 75 डॉलर पार करने के बाद और आगे बढ़ा है। बेहतर डिमांड आउटलुक से क्रूड में जोश बरकरार है। एशिया और यूरोप में स्पॉट प्रीमियम कई महीनों की ऊंचाई पर पहुंच गया है। जानकार अब क्रूड के लिए 100 डॉलर तक के लक्ष्य देने लग गए हैं लेकिन क्या फंडामेंटल्स इन लक्ष्यों को जायज ठहराते हैं। सोने में आज छोटे दायरे में कारोबार हो रहा है लेकिन चांदी में रिकवरी दिख रही है। मेटल्स में बढ़त के कारण चांदी को सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा फेड चेयरमैन की Testimony से भी प्रेसियस मेटल्स सहारा है। ब्रेंट अप्रैल, 2019 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर नजर आ रहा है। बेहतर डिमांड आउटलुक से क्रूड में जोश भरा है। ळए क्रूड इंवेंट्री में लगातार 5 हफ्ते गिरावट देखने को मिल रही है। ब्रेंट, WTI की कीमतों में अंतर 7 महीने में सबसे कम है। ईरान की सप्लाई जल्द बाजार में आने की उम्मीद नहीं है। एशिया, यूरोप में स्पॉट प्रीमियम कई महीनों की ऊंचाई पर है. Total के CEO ने ब्रेंट के 100 डॉलर तक जाने की बात कही है।

मूडीज ने 2021 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 9.6 प्रतिशत किया

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने बुधवार को वर्ष 2021 के लिए भारत के वृद्धि अनुमान को घटाकर 9.6 प्रतिशत कर दिया है, जो पिछले अनुमान के मुताबिक 13.9 प्रतिशत था। मूडीज ने साथ ही कहा कि तेजी से टीकाकरण के कारण जून तिमाही में आर्थिक प्रतिबंध सीमित होंगे। मूडीज ने 'व्यापक अर्थशास्त्र- भारतः कोविड की दूसरी लहर से आर्थिक झटके पिछले साल की तरह गंभीर नहीं होंगे' शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा कि उच्च आवृत्ति वाले आर्थिक संकेतक बताते हैं कि कोविड की दूसरी लहर ने अप्रैल और मई में भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। हालांकि, राज्यों द्वारा प्रतिबंधों में ढील देने के साथ इसमें सुधार की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया कि वायरस की वापसी से 2021 में भारत के वृद्धि पूर्वानुमानों को लेकर अनिश्चितता बढ़ी है, हालांकि यह संभावना है कि आर्थिक नुकसान अप्रैल-जून तिमाही तक ही सीमित रहेगा। मूडीज ने आगे कहा, ''हमें वर्ष 2021 में भारत की वास्तविक जीडीपी 9.6 प्रतिशत और 2022 में सात प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है।'' भारतीय अर्थव्यवस्था 2020-21 में 7.3 प्रतिशत घटी है, जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष के दौरान चार प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

महंगाई: पेट्रोल-डीजल की कीमतों से जनता परेशान

पेट्रोलियम मंत्री प्रधान ने बताया तेजी का कारण

एजेंसी। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने आसमान छू लिया है। कोरोना काल में पेट्रोल की कीमतों ने लोगों को हलकान किया हुआ है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान

ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ने की वजह से घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भारत में ईंधन की कीमतों में वृद्धि के पीछे मुख्य कारणों में से एक यह है कि हमें 80 फीसदी तेल आयात करना पड़ता है। प्रधान ने यह भी बताया कि अर्थशास्त्रियों ने एक मुद्दा उठाया है कि कांग्रेस ने पुनर्भुगतान के लिए करोड़ों के तेल बांड छोड़े थे, जिसके कारण हमें अब इसका ब्याज और इसकी मूल कीमत दोनों चुकानी पड़ रही है, यह भी ईंधन की कीमतों में वृद्धि का एक बड़ा कारण है।

वाहन ईंधन कीमतों में एक महीने में 29वीं बार बढ़ोतरी के बाद देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें नई ऊंचाई पर हैं। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज पेट्रोल व डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। कल डीजल की कीमत अधिकतम 26 से 28 पैसे तक बढ़ी थी तो वहीं पेट्रोल की कीमत भी 27 से 28 पैसे तक बढ़ी थी। आज अंतरराष्ट्रीय तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.60 फीसदी बढ़कर 75.26 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा।

लगातार बढ़ रहे ईंधन के दामों को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर होता जा रहा है। जनता भी सरकार से इसका कारण पूछ रही है। मालूम हो कि आज दिल्ली में पेट्रोल का दाम 97.50 रुपये जबकि डीजल का दाम 88.23 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.63 रुपये व डीजल की कीमत 95.72 रुपये प्रति लीटर है।

मई में 6.3 फीसदी कम हुआ कच्चा तेल उत्पादन

देश के कच्चा तेल उत्पादन में मई में 6.3 फीसदी कमी आई है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ओएनजीसी का उत्पादन चक्रवात 'ताउते' की वजह से माह के दौरान यह कम रहा है। सरकारी आंकड़ों में मंगलवार को यह जानकारी सामने आई है। कच्चे तेल का उत्पादन मई 2021 में 24.30 लाख टन रहा है जो कि इससे पिछले साल मई में हुये 26 लाख टन उत्पादन के मुकाबले 6.32 फीसदी कम रहा है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों में यह कहा गया है।

भारत का कच्चा तेल उत्पादन मई में 6.3 प्रतिशत घटा, गैस उत्पादन में उछाल

नयी दिल्ली। एजेंसी

देश के कच्चा तेल उत्पादन में मई में 6.3 प्रतिशत कमी आई है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ओएनजीसी का उत्पादन चक्रवात 'तउकते' की वजह से माह के दौरान करीब दस प्रतिशत कम रहा है। सरकारी आंकड़ों में मंगलवार को यह जानकारी सामने आई है। कच्चे तेल का उत्पादन मई 2021 में 24.30 लाख टन रहा है जो कि इससे पिछले साल मई में हुये 26 लाख टन उत्पादन के मुकाबले 6.32 प्रतिशत कम रहा है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों में यह कहा गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी) के कच्चे तेल उत्पादन में मई के दौरान 9.63 प्रतिशत की बड़ी गिरावट दर्ज की गई और यह 15 लाख टन रहा। चक्रवात तौकते से बनी कठिन परिस्थितियों के कारण उत्पादन में कमी आई है। ओएनजीसी के तेल एवं गैस उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र पश्चिमी अपतटीय इलाकों में ही स्थित है जहां पिछले महीने चक्रवाती तूफान के कारण आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुईं।

वहीं देश का गैस उत्पादन मई के दौरान 19 प्रतिशत बढ़कर 2.74 अरब घनमीटर तक पहुंच गया। देश के पूर्वी अपतटीय क्षेत्र में केजी डी6ब्लॉक से गैस उत्पादन बढ़ने से यह वृद्धि हासिल की गई है। इस ब्लॉक से रिलायंस- बीपी ने नई खोजों के जरिये गैस उत्पादन शुरू किया है।

बहरहाल, लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील दिये जाने के साथ ही मांग बढ़ने से रिफाइनरियों में कच्चे तेल शोधन में 16 प्रतिशत वृद्धि हुई और यह 1.90 करोड़ टन तक पहुंच गया। इस दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियों ने जहां स्थापित क्षमता के 91 प्रतिशत पर काम किया वहीं रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी ने क्षमता के मुकाबले 83.7 प्रतिशत पर काम किया।

सेंसेक्स 283 अंक लुढ़का निफ्टी 15700 के नीचे बंद

मुंबई। एजेंसी

बीएसई सेंसेक्स बुधवार को शुरूआती बढ़त को बरकरार नहीं रख सका और 283 अंक लुढ़क कर बंद हुआ। सूचकांक में मजबूत हिस्सेदारी रखने वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में गिरावट से बाजार नीचे आया। तीस शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 282.63 अंक यानी 0.54 प्रतिशत की गिरावट के साथ 52,306.08 अंक पर बंद हुआ। इसी प्रकार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 85.80 अंक यानी 0.54 प्रतिशत टूट कर 15,686.95 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में एक प्रतिशत से अधिक गिरावट के साथ सर्वाधिक नुकसान में कोटक बैंक का शेयर रहा।

सेंसेक्स के शेयरों में एक प्रतिशत से अधिक गिरावट के साथ सर्वाधिक नुकसान में कोटक बैंक का शेयर रहा। इसके अलावा एल एंड टी, टाटा स्टील, एचडीएफसी, टीसीएस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचसीएल टेक और आईसीआईसीआई बैंक भी नुकसान में रहे। दूसरी तरफ, मारुति, टाइटन, बजाज फिनसर्व और महिंद्रा एंड महिंद्रा समेत अन्य शेयर लाभ में रहे। एशिया के अन्य बाजारों में शंघाई, हांगकांग और तोक्यो लाभ में रहे जबकि सोल के बाजार में गिरावट रही। शुरूआती कारोबार में यूरोप के प्रमुख शेयर बाजारों में गिरावट का रुख रहा। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.84 प्रतिशत मजबूत होकर 75.44 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।

रुपये में दो दिन से जारी गिरावट थमी, 10 पैसे बढ़कर 74.27 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ

मुंबई। एजेंसी

रुपये में दो दिन से जारी गिरावट पर ब्रेक लग गया। विदेशी बाजारों में अमेरिकी मुद्रा में कमजोरी के रुख के बाद अन्तरबैंक विदेशीमुद्रा विनिमय बाजार में बुधवार को रुपया 10 पैसे मजबूत होकर 74.27 (अस्थायी) प्रति डालर पर बंद हुआ। अन्तरबैंक विदेशीमुद्रा विनिमय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर 74.26 पर खुली तथा दिन के कारोबार के दोरान 74.07 रुपये प्रति डालर के दिन के उच्च स्तर और 74.39 के निम्न स्तर को छूने के बाद अंत में रुपया 10 पैसे बढ़कर 74.27 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ। रुपया मंगलवार को प्रति डालर 74.37 पर बंद हुआ था। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.01 प्रतिशत घटकर 91.74 रह गया। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा 0.95 प्रतिशत बढ़कर 75.52 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। शेयर बाजार आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशक पूंजी बाजार में शुद्ध बिकवाल रहे और उन्होंने मंगलवार को सकल आधार पर 1,027.94 करोड़ रुपये के शेयरों की कटान की।

सऊदी अरब आखिर पाकिस्तान से तेल समझौता करने को क्यों तैयार हुआ?

एजेंसी

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए एक अहम समझौते के तहत सऊदी अरब हर साल पाकिस्तान को 1.5 अरब डॉलर के कच्चे तेल की मदद फिर से शुरू करने के लिए तैयार हो गया है। इसके आलावा सऊदी अरब पाकिस्तान में निवेश की योजना पर भी फिर काम शुरू करेगा।

ये समझौता इसी साल जुलाई से लागू होगा

नवंबर 2018 में सऊदी अरब पाकिस्तान को कुल 6.2 अरब डॉलर का कर्ज़ और ऑयल क्रेडिट (3.2 अरब डॉलर) देने को तैयार हुआ था। लेकिन कश्मीर के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच बात बिगड़ गई। भारत ने अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 370 को हटा दिया। पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर के मुद्दे पर उसे अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिले और इसके लिए उसने सऊदी पर दवाब बनाया। दोनों मुल्कों के बीच बात यहीं से बिगड़नी शुरू हुई। अगस्त 2020 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को क़र्ज़ की एक तय रकम लौटाने को ही नहीं कहा, बल्कि उसे दिया जाने वाले ऑयल क्रेडिट भी रद्द कर दिया।

क्या है वजह?

कुछ हलकों में ये चर्चा है कि पाकिस्तान के साथ फिर से हाथ मिला कर सऊदी अरब ईरान के प्रभुत्व को चुनौती देना चाहता है। लेकिन जानकार मानते हैं कि एक बार फिर पास आने के दोनों देशों के फ़ैसले को मौजूदा वक्त के बदलते भू-राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनज़र देखा जाना चाहिए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच ऐतिहासिक तौर पर रिश्ते अच्छे रहे हैं। दोनों का रिश्ता दशकों पुराना है, दोनों के बीच सुरक्षा मामलों के समझौते हैं और शीत युद्ध के दौरान दोनों साथ रहे हैं।

सऊदी अरब में भारत के राजदूत रहे तलमीज़ अहमद कहते हैं कि 1950 के दशक से दोनों के बीच रक्षा संबंध रहे हैं, जो कमज़ोर नहीं हुए हैं। पुराने रिश्ते होने के कारण दोनों में कभी-कभी थोड़ा-बहुत फ़र्क आना स्वाभाविक है, लेकिन उनका बुनियादी रिश्ता कभी टूटता नहीं हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान की तुलना में सऊदी अरब के साथ भारत के रणनीतिक तौर पर अहम संबंध हैं लेकिन ये रिश्ते अधिक पुराने नहीं हैं। दोनों के रिश्तों में प्राथमिकता निवेश और सुरक्षा है और सऊदी इस पर भी समझौता नहीं करेगा। यही कारण है कि एक तरफ़ जब वो पाकिस्तान के साथ भी रिश्ते बेहतर कर रहा है, तो दूसरी तरफ़ भारत के साथ भी वो संबंध बेहतर करने की कोशिश में है।

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पश्चिम एशिया और मध्यपूर्व मामलों के विशेषज्ञ प्रोफ़ेसर एके पाशा कहते हैं कि इसके पीछे बड़ी वजह हाल के वक़्त में आए बदलाव हैं। वो बताते हैं, 'जमाल ख़ाशोज्जी की हत्या और डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद सऊदी अरब की घरेलू राजनीति में काफ़ी बदलाव आए हैं। ट्रंप के शासनकाल में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को अमेरिका से मदद मिलती रही थी, लेकिन बाइडन के आने के बाद सऊदी अरब और ईरान के लिए अमेरिका की विदेश नीति में 180 डिग्री का बदलाव आया है।'

'दूसरी तरफ सऊदी अरब को उम्मीद थी कि रक्षा मामलों में इसराइल के साथ उसके रिश्ते बेहतर होंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। ऐसे में प्राकृतिक तौर पर पाकिस्तान उसके लिए अहम हो गया। वैसे भी पाकिस्तान ज़रूरत पड़ने पर फौजें भेज कर सऊदी की मदद करता रहा है और वो पहले से पाकिस्तान को एक बड़े मददगार के रूप में देखता रहा है।'

केबिनेट की मिली मंजूरी

PSU: इन दो पीएसयू कंपनियों का हो जाएगा विलय

नई दिल्ली। एजेंसी

केन्द्र सरकार ने कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निजी क्षेत्र की दक्षता का उपयोग करने की दिशा में एक और कदम उठाया है। सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम 'सेंट्रल रेलसाइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड' (CRWC) की सभी संपत्तियों, देनदारियों, अधिकारों और दायित्वों को अपने होल्डिंग उद्यम 'सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन' के साथ ट्रान्सफर करने और विलय को मंजूरी दे दी है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। सीआरडब्ल्यूसी को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 2007 में एक मिनी रत्न श्रेणी-II में शामिल किया गया था।

इस विलय से एक ही प्रशासन के माध्यम से न सिर्फ दोनों कंपनियों के वेयरहाउसिंग, हैंडलिंग और परिवहन जैसे समान कार्य एकीकृत होंगे बल्कि इनकी दक्षता, इष्टतम क्षमता उपयोग, पारदर्शिता, जवाबदेही को बढ़ावा देने के साथ-साथ वित्तीय बचत को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसके अलावा नई वेयरहाउसिंग क्षमताओं के लिए रेलवे साइडिंग का लाभ उठाया जा सकेगा।

5 करोड़ रुपये की होगी बचत

अनुमान है कि रेलसाइड वेयरहाउस कॉम्प्लेक्स (RWC) के प्रबंधन व्यय में कॉर्पोरेट कार्यालय के किराए, कर्मचारियों के वेतन और अन्य प्रशासनिक लागतों में बचत के कारण 5 करोड़ रुपये की कमी आएगी। आरडब्ल्यूसी के क्षमता उपयोग में भी सुधार होगा क्योंकि सीडब्ल्यूसी के लिए सीमेंट, उर्वरक, चीनी, नमक और सोडा जैसी वर्तमान वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुओं के भंडारण की क्षमता में भी वृद्धि होगी। इस विलय से माल-गोदाम स्थलों के पास कम से कम 50 और रेलसाइड गोदाम स्थापित करने की सुविधा मिलेगी। इससे कुशल कामगारों के लिए 36,500 और अकुशल कामगारों के लिए 9,12,500 श्रम दिवसों के बराबर रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। इस विलय की पूरी प्रक्रिया निर्णय की तिथि से 8 महीने के भीतर पूरा होने की उम्मीद है।

10 जुलाई 2007 को हुआ सीआरडब्ल्यूसी का गठन

सीडब्ल्यूसी 1957 में स्थापित एक मिनी रत्न श्रेणी-ध सीपीएसई है। यह केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कृषि उपज और कुछ अन्य वस्तुओं के भंडारण के उद्देश्य व उससे जुड़े मामलों के लिए वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के निगमन और विनियमन के लिए सेवाएं प्रदान करती है। सीडब्ल्यूसी एक लाभ कमाने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, जिसकी अधिकृत पूंजी 100 करोड़ रुपये और चुकता पूंजी 68.02 करोड़ रुपये है। सीडब्ल्यूसी ने 10 जुलाई 2007 को 'सेंट्रल रेलसाइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड' (ण्ैंण्) नामक एक अलग सहायक कंपनी का गठन किया, जो रेलवे से पट्टे पर ली गई थी और यह अधिग्रहित भूमि पर रेलसाइड वेयरहाउसिंग कॉम्प्लेक्स/टर्मिनलों/मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स हब की योजना, विकास, प्रचार, अधिग्रहण और संचालन करती है।

50 कर्मचारी और 48 आउटसोर्स कर्मी

सीआरडब्ल्यूसी 50 कर्मचारियों और 48 आउटसोर्स कर्मियों की क्षमता के साथ एक छोटा संगठन है। वर्तमान में, यह देश भर में 20 रेलसाइड वेयरहाउसों को संचालित कर रही है। 31 मार्च 2020 तक, कंपनी की निवल संपत्ति 137.94 करोड़ रुपये (निर्बाध आरक्षित निधियों के अलावा चुकता पूंजी) है। चूंकि सीडब्ल्यूसी, सीआरडब्ल्यूसी का एकमात्र शेयरधारक है इसलिए सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों, अधिकारों और दायित्वों को सीडब्ल्यूसी को हस्तांतरित करने से दोनों में से किसी को भी कोई वित्तीय नुकसान नहीं होगा बल्कि इस निर्णय से दोनों के बीच एक बेहतर तालमेल स्थापित होगा। आरडब्ल्यूसी के संचालन और मार्केटिंग को संभालने के लिए सीडब्ल्यूसी द्वारा 'आरडब्ल्यूसी प्रभाग' नाम से एक अलग प्रभाग का गठन किया जाएगा।

युवाओं के उत्साह से इंदौर ने रचा एक ही दिन में 2.25 लाख टीके लगाने का कीर्तिमान

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में एक ही दिन में 2.25 लाख लोगों को कोविड-19 रोधी टीके लगाने का राष्ट्रीय कीर्तिमान रचे जाने के पीछे इसकी पहली खुराक लेने का लम्बे समय से इंतजार कर रहे युवाओं की बड़ी भूमिका रही है। इंदौर, राज्य में महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है जहां सोमवार से टीकाकरण का महाअभियान शुरू किया गया। जिला टीकाकरण अधिकारी प्रवीण जड़िया ने मंगलवार को पीटीआई-भाषा को बताया, 'अंतिम आंकड़ों के मुताबिक जिले में सोमवार को 2,25,676 लोगों को टीके लगाए गए। यह देश भर के किसी भी जिले में एक ही दिन में सर्वाधिक टीकाकरण का राष्ट्रीय कीर्तिमान है।' उन्होंने बताया कि सोमवार को 18 से 44 वर्ष के 1,70,133 लोगों को टीके की पहली खुराक दी गई, जबकि इस दिन उक्त आयु वर्ग में टीके की दूसरी खुराक लेने वाले

व्यक्तियों की तादाद केवल 240 थी। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि सोमवार को जिले में टीका लगवाने वाले लोगों में 75.5 फीसद 18 से 44 वर्ष के थे। चश्मदीदों ने बताया कि जिले के टीकाकरण केंद्रों पर सोमवार को युवाओं की लम्बी कतारें देखी गई थीं। इस बीच, राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौरवासियों की तारीफ करते हुए एक बयान में कहा, 'कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण में इंदौर की जनता का उत्साह सराहनीय है। पूरे देश में स्वच्छता के क्षेत्र में प्रथम पायदान पर रहने वाला इंदौर अब टीकाकरण में भी अव्वल हो गया है।' मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, 'हमें अभी रुकना नही है। जब तक हम 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को टीका नहीं लगा देते, तब तक टीकाकरण का महा अभियान जारी रहना चाहिए।' अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन ने इंदौर जिले में सोमवार को दो लाख लोगों को टीके लगाने का लक्ष्य तय किया था। इसे हासिल करने के लिए 675 टीकाकरण केंद्र बनाए गए जहां कुल 1,140 सत्रों में सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक टीके लगाए गए। उन्होंने बताया कि जिले में सोमवार को करीब 1,200 स्वास्थ्य कर्मियों ने टीके लगाने का जिम्मा संभाला और 40 केंद्रों से टीकों का वितरण किया गया, जबकि 120 डॉक्टरों ने टीकाकरण महा अभियान की निगरानी की। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 35 लाख की आबादी वाले जिले में अब तक कोविड-19 के कुल 1,52,776 मरीज मिले हैं। इनमें से 1,377 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है।

क्या जीएसटी के दायरे में आएगा पेट्रोल-डीजल, जानिए हाईकोर्ट ने क्या दिया जवाब?

नई दिल्ली। एजेंसी

आम आदमी को तेल के बढ़ते दाम से राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल को गुड्स एंड सर्विसज टैक्स के दायरे में लाए जाने की मांग की जा रही है। हालांकि, जीएसटी में पेट्रोल, डीजल के शामिल करने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। इस बीच, केरल हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी सिस्टम के तहत लाने की मांग करने वाले एक प्रतिनिधित्व पर फैसला करने को कहा है।

चीफ जस्टिस एस मणिकुमार और जस्टिस Shaji P Chaly की खंडपीठ ने सरकार से 6 हफ्ते के भीतर इस पर फैसला लेने को कहा है। केरल प्रदेश गांधी दर्शनवेदी ने एडवोकेट अरुण बी वर्गीस के माध्यम से पेट्रोल, डीजल को जीएसटी में शामिल किए जाने की याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि विभिन्न राज्यों में पेट्रोल और डीजल की दरें अलग-अलग हैं क्योंकि प्रत्येक राज्य द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स अलग है।

बता दें कि पेट्रोलिमय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेट्रोल, डीजल को माल एवं सेवाकर (उएऊ) के दायरे में लाने के बारे में कोई भी फैसला जीएसटी काउंसिल (उएऊ ण्दल्हम्त) को लेना है। देश के कई शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर से ऊपर पहुंच गए हैं।

जून में 3 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। मंगलवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 27-28 पैसे प्रति लीटर और डीजल के भाव में 26.28 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया है। इस बढ़ोतरी के बाद मुंबई में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 103.63 रुपए हो गई जबकि एक लीटर डीजल का भाव 95.72 रुपए हो गया। इस महीने पेट्रोल और डीजल के दाम में 3 रुपए से ज्यादा का उछाल आया है। वहीं, 3 मई से इसमें 8 रुपए प्रति लीटर की तेजी आई है जबकि साल 2021 में पेट्रोल-डीजल 15.20 रुपए तक महंगा हुआ है।

रिपोर्ट के मुताबिक, याचिकर्ता याचिका पेट्रोल और डीजल टैक्स का यूनिफिकेशन की मांग की है। उसने याचिका में आरोप लगाया था कि लगातार तेल की बढ़ती कीमतें आम आदमी के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है क्योंकि आम सामानों की कीमतें भी तेल की बढ़ती कीमतों में बढ़ोतरी के साथ बढ़ती हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा था कि केंद्र और राज्य सरकारें तेल की कीमतों को नियंत्रित और हस्तक्षेप करती हैं। जब चुनाव आते हैं तो तब भी वे कहते हैं कि यह पेट्रोल मार्केटिंग कंपनियां तेल की कीमतें तय करती हैं।

ब्रांड न्यू के बजाय सेकंड हैंड स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं लोग

नई दिल्ली। एजेंसी

सेकंड हैंड और रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन (RefuRished Smartphone) मार्केट कोविड19 की दूसरी लहर (Coronavirus Second Wave) की मार से पूरी तरह उबर चुका है। लोगों की ओर से सेकंड हैंड स्मार्टफोन की खरीद की जा रही है क्योंकि महामारी की वजह से वे अभी कम कीमत पर मिलने वाली क्वालिटी डिवाइस खरीदने को प्राथमिकता दे रहे हैं। आलम यह है कि दूसरी लहर के बाद यूज्ड स्मार्टफोन की मांग में रिकवरी, नए स्मार्टफोन की मांग में रिकवरी से तेज है। लेकिन कंपनियों का कहना है कि कंपोनेंट की कमी और बढ़ती लागत ने रिफर्बिशिंग सेकंड हैंड डिवाइसेज में व्यवधान पैदा किया है।

दूसरी लहर में 55 फीसदी गिरी थी बिक्री

स्मार्टफोन और एक्सेसरीज के रिकॉमर्स मार्केट प्लेस कैशिफाई का कहना है कि कोविड19 की दूसरी लहर के दौरान बिक्री 55 फीसदी गिरी थी लेकिन जून में बिक्री ट्रैक पर लौट आई है और मार्च के बिक्री आंकड़ों के पार जा चुकी है। OLX के मुताबिक, सेकंड हैंड स्मार्टफोन और लैपटॉप की मांग पूरी तरह से रिकवर होकर 2021 की पहली तिमाही वाले लेवल पर पहुंच चुकी है।

OLX का कहना है कि मार्च और अप्रैल में यूज्ड स्मार्टफोन की मांग में 14 फीसदी की कमी आई थी लेकिन मई में मांग पूरी तरह से रिकवर हो गई। टैबलेट के मामले में मार्च और अप्रैल में गिरी मांग मई माह में सुधरी और जनवरी में मांग के स्तर को भी पार कर गई।

आने वाले महीनों में मांग में हो सकती है दोगना वृद्धि

रिकॉमर्स मार्केटप्लेस Xtracover.com का स्वामित्व रखने वाले Aforeserve Group के मुताबिक, रिफर्बिश्ड डिवाइसेज बिजनेस के आने वाले महीनों में दोगुना बढ़ने की संभावना है। इसकी वजह है कि प्रतिबंधों में ढील के बाद ग्राहकों ने ऑर्गेनाइज्ड रिफर्बिश्ड कंपनियों से सर्टिफाइड प्रॉडक्ट खरीदने में रुचि दिखाई है। प्रीओन्ड यानी सेकंड हैंड स्मार्टफोन मार्केट में Mi सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड है। इसकी बाजार हिस्सेदारी 26 फीसदी है। इसके बाद 20 फीसदी बाजार हिस्सेदारी के साथ एप्पल, 16 फीसदी के साथ सैमसंग, 6 फीसदी के साथ मोटोरोला, 6 फीसदी के साथ वीवो और 5 फीसदी बाजार हिस्सेदारी के साथ ओप्पो है।

आर्थिक अनिश्चितता में ग्राहक पैसे बचाने पर करते हैं फोकस

OLX India के प्रवक्ता कहते हैं कि जब भी आर्थिक अनिश्चितता (Economic Uncertainty) का माहौल होता है, लोग सेकंड हैंड सामान लेने में रुचि दिखाने लगते हैं क्योंकि वे अपने पैसों को बचाकर रखना चाहते हैं और इसलिए खर्च कम कर देते हैं। कोविड की पहली और दूसरी लहर के दौरान हमने सेकंड हैंड सामानों की मांग में, नए सामान (Fresh Units) की मांग के मुकाबले ज्यादा तेजी देखी।

ITR फाइल नहीं किया? 1 जुलाई से चुकाना पड़ सकता है दोगुना टीडीएस

नई दिल्ली। एजेंसी

वित्त अधिनियम, 2021 के अनुसार 1 जुलाई से इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) नहीं भरने वालों के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली है। उनके ऊपर उच्च टीडीएस/टीसीएस दर लागू होगी यानी उन्हें ऊअए/ऊएए अधिक चुकाना पड़ेगा। इनकम टैक्स विभाग ने 21 जून को कहा कि उसने टीडीएस (स्रोत पर टैक्स कटौती) काटने और टीसीएस (स्रोत पर टैक्स कलैक्शन) संग्रह करने वालों के लिए उन व्यक्तियों की पहचान करने में मदद की एक नई व्यवस्था तैयार की है, जिन पर 1 जुलाई से ऊंची दर से टैक्स वसूला जाएगा।

वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में यह प्रावधान किया गया है कि पिछले दो वित्त वर्षों में इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने वाले उन लोगों के मामले में स्रोत पर टैक्स कटौती और स्रोत पर टैक्स कलैक्शन अधिक रेट से होगा, जिन पर दो वर्षों में प्रत्येक में 50,000 रुपए या उससे अधिक टैक्स कटौती बनती है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सर्कुलर टैक्स रिटर्न नहीं भरने वाले ऐसे लोगों के मामले में उच्च दर से टैक्स कटौती/संग्रह को लेकर धारा 206AB और 206CCA के क्रियान्वयन को लेकर सर्कुलर जारी किया।

टीसीएस संग्रह के लिए, अधिनियम की धारा 206CCA के तहत दर इससे अधिक होगी। संबंधित अनुभाग में निर्दिष्ट दर से दोगुना या 5 प्रतिशत होगा।

इन मामलों में लागू नहीं होगा नया नियम

हालांकि, धारा 192A के तहत वेतन या भविष्य निधि से निकासी के लिए धारा 192 के तहत काटे गए ऊअए के लिए नई लागू धारा 206AB लागू नहीं होगी। धारा 194B या 194BB के तहत कार्ड गेम, क्रॉसवर्ड, लॉटरी, पहेली या किसी अन्य गेम और घुड़दौड़ से जीतने पर TDS नए सेक्शन के दायरे में नहीं आएगा। यह धारा 194N के तहत 1 करोड़ रुपए से अधिक नकद निकासी और धारा 194LBC के तहत प्रतिभूतिकरण ट्रस्ट में निवेश के खिलाफ आय पर TDS के लिए लागू नहीं होगा।

इनकम टैक्स विभाग ने ट्विटर पर लिखा है कि धारा 206AB और 206CCA के लिए अनुपालन जांच को लेकर नई व्यवस्था जारी की गई है। इससे स्रोत पर टैक्स काटने वाले तथा ऊएए संग्रहकर्ता के लिए अनुपालन बोझ कम होगा। CBDT ने कहा कि चूंकि TDS काटने वाले या ऊएए संग्रहकर्ता को व्यक्ति की पहचान को लेकर इस पर उचित ध्यान और कार्य करने की आवश्यकता होगी, अतः इससे उन पर अतिरिक्त अनुपालन बोझ पड़ सकता है। बोर्ड ने कहा कि नई व्यवस्था - धारा 206AB और 206CCA के लिए अनुपालन जांच - उन पर इस अनुपालन बोझ को कम करेगा। नई व्यवस्था के तहत TDS अथवा ऊएए संग्रहकर्ता को उस भुगतानकर्ता अथवा TCS देनदार का पैन प्रक्रिया में डालना है जिससे यह पता चल जायेगा कि वह विशिष्ट व्यक्ति है अथवा नहीं।

इनकम टैक्स विभाग ने 2021-22 की शुरुआत में विशिष्ट व्यक्तियों की लिस्ट तैयार कर ली है। यह लिस्ट तैयार करते समय 2018-19 और 2019- 20 को पिछले दो संबंधित वर्षों पर गौर किया गया है। इस लिस्ट में उन टैक्सपेयर्स के नाम हैं जिन्होंने आकलन वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए रिटर्न दाखिल नहीं की है और इन दोनों वर्ष में प्रत्येक में उनका कुल TDS और TCS 50000 रुपए या इससे अधिक रहा है।

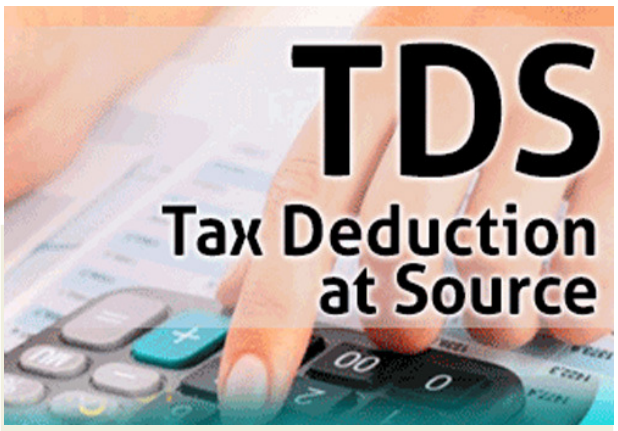

इनकम टैक्स अधिनियम 1961 की धारा 206AB के तहत, लगाया जाने वाला नया TDS दर उच्चतम होगाः-

■ इनकम टैक्स अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान में निर्दिष्ट दर से दोगुना होगा। ■ लागू दरों की दुगनी दर। ■ पांच प्रतिशत की दर से।

सरकार, उद्योग को सुनिश्चित करने की जरूरत, नियम-कानून निवेश को प्रभावित नहीं करेः बिजली सचिव

नयी दिल्ली। एजेंसी

केंद्रीय बिजली सचिव आलोक कुमार ने मंगलवार को कहा कि सरकार और उद्योग को यह सुनिश्चित करने के लिये मिलकर काम करना चाहिए कि मौजूदा नियम-कानून निवेश के रास्ते में बाधा उत्पन्न नहीं करे। उन्होंने सार्वजिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी द्वारा 'ऑनलाइन' आयोजित दो दिवसीय ब्रिक्स ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में यह बात कही। एनटीपीसी ने कुमार के हवाले से एक बयान में कहा, ''सरकार और उद्योग को यह सुनिश्चित करने के लिये मिलकर काम करने की आवश्यकता है कि नियम-कानून निवेश के रास्ते में अनावश्यक बाधा न हों।'' उन्होंने कहा कि बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन के सुरक्षित परिवहन और भंडारण तथा उत्पत्ति के उपयुक्त प्रमाण पत्र को लेकर सामान्य अंतरराष्ट्रीय मानकों से व्यापार को लाभ होगा। सचिव ने कहा कि ब्रिक्स देश इन पहलुओं पर मिलकर काम कर सकते हैं। कुमार ने कहा, ''भारत ने प्रतिस्पर्धी तरीके से हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिये महत्वकांक्षी राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है। इसके तहत निजी क्षेत्र से जुड़े उर्वरकों / रिफाइनरियों के लिए हरित हाइड्रोजन की खरीद अनिवार्य होगी।''

इस मौके पर एनटीपीसी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह ने कहा, ''पांच ब्रिक्स देश सतत विकास और समावेशी आर्थिक विकास का एक साझा दृष्टिकोण रखते हैं। ब्रिक्स देशों के एजेंडे में ऊर्जा सहयोग को मजबूत करना और सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, सुलभ और सुरक्षित ऊर्जा सुनिश्चित करना हमेशा से महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र रहा है।'' ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। सिंह ने कहा कि भारत हाइड्रोजन के बड़े स्तर पर अपनाने से न केवल हाइड्रोकार्बन ईंधन पर अपनी आयात निर्भरता को कम करेगा, बल्कि अपने नागरिकों को स्वच्छ हवा भी प्रदान करने के साथ ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाएगा और देश के 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण को पूरा करेगा।'' 'ऑनलाइल' कार्यक्रम में ब्रिक्स में शामिल सभी देशों के विशेषज्ञों ने विषय पर अपने विचार रखे और अस क्षेत्र में अपने-अपने देशों में हो रही ताजा गतिविधियों की जानकारी दी।

डाबर का एक कदम और साल में 150 टन पेपर की होगी बचत! जानें क्या करने जा रही है कंपनी

नई दिल्ली। एजेंसी

एफएमसीजी कंपनी डाबर ने अपने टूथपेस्ट के लिए पेपर पैकेजिंग से दूरी बनाने का फैसला किया है। यह कदम उठाने वाली डाबर पहली कंपनी है। डाबर इंडिया अपने टूथपेस्ट ब्रांड डाबर रेड पेस्ट की बाहरी पेपर पैकेजिंग यानी कार्टन को हटाने की दिशा में काम कर रही है। कंपनी रिलायंस रिटेल के साथ मिलकर प्रमुख मॉडर्न ट्रेड आउटलेट्स में इस दिशा में एक पायलट चला रही है।

डाबर में वाइस प्रेसिडेंट (मार्केटिंग-पर्सनल केयर) राजीव जॉन का कहना है कि डाबर टूथपेस्ट पर पेपर पैकेजिंग को लेकर उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया के जवाब में यह पायलट शुरू किया गया है। डाबर के इस कदम से सालाना 150 टन पेपर की बचत होने की उम्मीद है।

गांवों के लिए पेश कर रही लो यूनिट प्राइस पैक

इसके अलावा डाबर ग्रामीण भारत के लिए एक बिना कार्टन वाला लो यूनिट प्राइस पैक भी उतार रही है। इससे पहले यूनीलीवर जैसी कंपनियों ने डव साबुन के बॉक्स से प्लास्टिक लेयर हटाने और पॉन्ड्स टैल्क की पैकेजिंग में सिंगल यूज प्लास्टिक कम करने जैसे कदम उठाए थे।

कमजोर मांग के कारण रिफाइंड सोया तेल वायदा कीमतों में गिरावट

नयी दिल्ली। एजेंसी

हाजिर बाजार की कमजोर मांग के बीच सटोरियों ने अपने सौदों के आकार को घटाया जिससे वायदा कारोबार में बुधवार को रिफाइंड सोया तेल का दाम 5.9 रुपये की गिरावट के साथ 1,263.5 रुपये प्रति 10 किग्रा रह गया। नेशनल कमोडिटी एण्ड डेरिवेटिव्ज एक्सचेंज में जुलाई माह में डिलीवरी के लिये रिफाइंड सोया तेल के वायदा अनुबंध का भाव 5.9 रुपये यानी 0.46 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,263.5 रुपये प्रति 10 किग्रा रह गया। इस अनुबंध में 35,685 लॉट के लिये सौदे किये गये।बाजार विश्लेषकों ने कहा कि पर्याप्त स्टॉक के मुकाबले कारोबारियों द्वारा अपने सौदों की कटान करने से यहां वायदा कारोबार में रिफाइंड सोया तेल कीमत में गिरावट दर्ज हुई। रिफाइंड सोया तेल के अगस्त माह में डिलीवरी के लिये वायदा अनुबंध का भाव 7.2 रुपये यानी 0.58 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,240 रुपये प्रति 10 किग्रा रह गया। इस अनुबंध में 9,470 लॉट के लिये सौदे किये गये।

डॉलर नहीं, ये है दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी, जानिए कौन हैं टॉप 5 मुद्रा

डॉलर से बारे में हम रोज सुनते रहते हैं। लेकिन यह दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी नहीं है। आइए यहां जानते हैं दुनिया की 5 सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है।

जब भी दुनिया की सबसे मजबूत मुद्राओं (करेंसी) की बात आती है तो हमारे जेहन में हमेशा डॉलर आता है क्योंकि हम रोज सुनते और पढ़ते हैं कि हमारा रुपए डॉलर की तुलना में कितना चढ़ गया है और कितना गिर गया है। लेकिन डॉलर सबसे मजबूत करेंसी नहीं है। तो आइए जानते हैं सबसे मजबूत करेंसी कौन है? गौर हो कि संयुक्त राष्ट्र ने करीब 180 मुद्राओं को लिगल टेंडर के तौर पर मान्यता दी है। दुनिया भर में करेंसी के मूल्य में नियमित रूप से उतार-चढ़ाव होता रहता है। कुछ मुद्राओं को दूसरों की तुलना में अधिक शक्तिशाली माना जाता है। आइए जानते हैं दुनिया में टॉप 5 सबसे मजबूत करेंसी कौन-कौन है।

दुनिया की नंबर 1 सबसे मजबूत करेंसी- कुवैती दीनार (KWD)

कुवैती दीनार (KWD) देश की आधिकारिक मुद्रा है। दीनार नाम रोमन दीनार से आया है। कुवैती दीनार को 1000 फिल्स में विभाजित किया गया है, एक सिक्का जो कई अरब देशों में इस्तेमाल किया जाता है। कुवैती दीनार को व्यापक रूप से दुनिया की सबसे शक्तिशाली मुद्रा माना जाता है। कुवैती दीनार को संक्षेप में KWD भी कहते हैं। मध्य पूर्व में तेल से संबंधित लेनदेन में इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। कुवैती दीनार मई 2021 तक सबसे मजबूत सर्कुलेटिंग करेंसी है। जिसमें 1 कुवैती दीनार 3.32 अमेरिकी डॉलर के बराबर है। यानी एक कुवैती दीनार 246 रुपए के बराबर है। कुवैती दिनार (KWD) को 1961 में खाड़ी रुपए के बदले में पेश किया गया था। खाड़ी का रुपया भारतीय रुपए से जुड़ी करेंसी थी।

1959 में भारत सरकार द्वारा जारी गल्फ रुपया, मुख्य रूप से फारस की खाड़ी क्षेत्र में भारत के बाहर उपयोग के लिए अभिप्रेत था। खाड़ी का रुपया, भारतीय रुपए की तरह, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग (GBP) से आंका गया था।

दुनिया की नंबर 2 सबसे मजबूत करेंसी- बहरीन दीनार

बहरीन दीनार दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान सर्कुलेटिंग करेंसी है, जिसमें एक बहरीन दीनार 2.65 अमेरिकी डॉलर के बराबर है, जो कुवैती दीनार से थोड़ा पीछे है, जिसकी कीमत 3.32 अमेरिकी डॉलर है। बहरीन फारस की खाड़ी में एक द्वीपीय देश है जिसकी आबादी 10 लाख से कुछ अधिक है। इसके राजस्व का प्राथमिक स्रोत, कुवैत की तरह, वैश्विक गैस और पेट्रोलियम निर्यात है। आश्चर्यजनक रूप से, बहरीन दिनार के साथ सऊदी रियाल को आधिकारिक तौर पर बहरीन में कानूनी करेंसी के तौर पर मान्यता प्राप्त है। उनकी विनिमय दर भी निर्धारित है, जिसमें 1 दीनार 10 रियाल के बराबर है।

दुनिया की नंबर 3 सबसे मजबूत करेंसी- ओमन रियाल

ओमान रियाल ओमान की नेशनल करेंसी है, जो अरब प्रायद्वीप पर स्थित है, और यह वर्तमान में दुनिया की सबसे मूल्यवान करेंसी में तीसरे स्थान पर है। 1940 से पहले ओमान की स्थानीय मुद्रा भारतीय रुपया थी, जिसे जल्दी से एक अधिक शक्तिशाली मुद्रा से बदल दिया गया था। ओमान की अर्थव्यवस्था ज्यादातर उसके तेल भंडार पर आधारित है, जो अरब प्रायद्वीप के दक्षिण-पूर्वी तट पर स्थित है। ओमानी रियाल अमेरिकी डॉलर से बंधा हुआ है।

दुनिया की नंबर 4 सबसे मजबूत करेंसी- जॉर्डन दीनार

जॉर्डन की आधिकारिक मुद्रा जॉर्डनियन दिनार (JOD) है। यह जॉर्डन नदी पर स्थित एक अरबी देश है। जॉर्डन की सरकार स्थिर विनिमय दरों को बनाए रखती है, जो मुद्रा के उच्च मूल्य के पीछे मुख्य कारणों में से एक है। जॉर्डन, अपने पड़ोसियों के विपरीत, तेल निर्यात पर अत्यधिक निर्भर नहीं है, जॉर्डन दिनार, जिसे 1949 में फिलिस्तीनी पाउंड को बदलने के लिए पेश किया गया था, पिछले दो दशकों से अमेरिकी डॉलर से बंधा हुआ है।

दुनिया की नंबर 5वीं सबसे मजबूत करेंसी- ब्रिटिश पाउंड

स्टर्लिंग यूनाइटेड किंगडम की नेशन करेंसी है। ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, दुनिया की सबसे मूल्यवान मुद्राओं में 5वें स्थान पर है। पाउंड स्टर्लिंग को अक्सर दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा माना जाता है। फिर भी, यह मजबूती के मामले में 4 अरबी करेंसी से पीछे है। यूनाइटेड किंगडम द्वारा यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के फैसले का पाउंड के मूल्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसके बावजूद, यह प्रचलन में दुनिया की सबसे पुरानी मुद्रा है और सबसे अधिक विनिमय में से एक है। केबल या जीबीपी/यूएसडी एफएक्स बाजार में तीसरी सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा जोड़ी है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पांच महीने और मुफ्त खाद्यान्न आवंटन को मंजूरी

नयी दिल्ली। एजेंसी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के चौथे चरण के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के लाभार्थियों को जुलाई से लेकर नवंबर 2021 तक पांच महीने की और अवधि के लिए मुफ्त खाद्यान्न आवंटन को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकारी बयान के अनुसार, एनएफएसए के तहत अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवार के तहत कवर किए गए 81.35 करोड़ लाभार्थियों को जुलाई से लेकर नवंबर, 2021 तक के लिए पांच किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से मुफ्त खाद्यान्न मिल सकेगा। इसमें कहा गया है कि 81.35 करोड़ व्यक्तियों को पांच महीने के लिए पांच किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त खाद्यान्न की मंजूरी से 64,031 करोड़ रुपये की अनुमानित खाद्य सब्सिडी की जरूरत होगी। बयान के अनुसार, चूंकि भारत सरकार इस योजना के लिए राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों के बिना किसी भी योगदान के पूरे खर्च को वहन कर रही है, भारत सरकार द्वारा परिवहन एवं ढुलाई और एफपीएस डीलरों के लाभांश आदि के लिए लगभग 3,234.85 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च किया जाएगा। इस प्रकार, भारत सरकार द्वारा वहन किया जाने वाला कुल अनुमानित व्यय 67,266.44 करोड़ रुपये होगा। इसमें कहा गया है कि गेहूं/चावल के रूप में आवंटन के बारे में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा तय किया जाएगा। खाद्यान्न के मामले में कुल निर्गम लगभग 204 लाख मीट्रिक टन हो सकता है। सरकार का कहना है कि इस अतिरिक्त आवंटन से कोरोना वायरस के कारण आए आर्थिक व्यवधान से गरीबों को होने वाली कठिनाइयों में कमी आएगी। अगले पांच महीने में किसी भी गरीब परिवार को व्यवधान की वजह से खाद्यान्न की अनुपलब्धता के कारण कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।

पर्यावरण अनुकूल सामग्री वाले खिलौने बनाने का आह्वान

नयी दिल्ली। एजेंसी

कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को देश में परिस्थितिकी की दृष्टि से स्वस्थ विनिर्माण सामग्री वाले खिलौने बनाने के वास्ते शोध संस्थाओं और खिलौना विनिर्माताओं को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि देश में 85 प्रतिशत खिलौने या तो आयात किये जाते हैं या फिर प्लास्टिक के बने होते हैं। ईरानी ने शिक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में काम करने वाली शोध संस्थाओं से स्वस्थ सामग्री के खिलौने बनाने की संभावनाओं को देखने के लिये कहा।

ईरानी ने और शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने मंगलवार को वीडियो कन्फ्रेंस के जरिये टॉयकाथोन 2021 के फाइनल का उद्घाटन किया। टॉयकाथोन 2021 को शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास, एमएसएमई, कपडा, सूचना एवं प्रसारण के साथ साथ उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने मिलकर 5 जनवरी 2021 को शुरू किया था। इसकी शुरुआत नवोन्मेषी खिलौने और खेल विचार प्राप्त करने के लिये किया गया था।

टॉयकाथोन 2021 के लिये देशभर से 1.2 लाख भागीदारों ने पंजीकरण कराया और 17,000 से अधिक नये विचार सौंपे गये। इसमें से तीन दिन तक चलने वाले ग्रांड फाइनल के लिये 1,567 नये विचारों और शोध को छांटा गया है। फाइनल 22 से 24 जून तक आयोजित होगा।

स्मृति ईरानी ने इस बात को लेकर चिंता जताई कि देश में बच्चे जिन खिलौनों से खेलते हैं उनमें से 85 प्रतिशत खिलौने या तो आयातित होते हैं या फिर इन्हें प्लास्टिक से बनाया होता है। भारत का खिलौना बाजार 1.5 अरब डालर का आंका गया है। जबकि वैश्विक खिलौना बाजार 100 अरब डालर से भी अधिक होने का अनुमान है। टॉयकाथोन 2021 में भाग लेने वालों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कन्फ्रेंस के जरिये 24 जून को बात करेंगे।

सैमसंग ने 6जी प्रौद्योगिकी में 5जी के मुकाबले 50 गुना ज्यादा तेज रफ्तार हासिल करने का दावा किया

नयी दिल्ली। एजेंसी

दक्षिण कोरिया की शीर्ष प्रौद्योगिकी कंपनी सैमसंग ने मंगलवार को 6जी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में 5जी के मुकाबले 50 गुना ज्यादा तेज रफ्तार हासिल करने का दावा किया। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और उत्पाद रणनीति, नेटवर्क व्यापार प्रमुख वोनिल रोह ने नये 5जी ट्रांसमिशन उपकरण से जुड़ी कंपनी की प्रस्तुति में कहा कि सैमसंग ने 5जी नेटवर्क पर 5.23 गिगाबिट प्रति सेकेंड (जीबीपीएस) की रफ्तार हासिसल की है। सैंमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के नेटवर्क व्यापार वरिष्ठ उपाध्यक्ष और उन्नत संचार अनुसंधान के प्रमुख सुंघयुन चोई ने कहा, '6जी उभरती विविध तकनीकों के साथ अवसरों की एक दुनिया का निर्माण करेगा जिससे उभरते अनुभवों एवं सेवाओं के प्रतिमान को पूर्ण आकार मिलेगा। हम 6जी को वास्तविकता का रूप देने के लेकर उत्साहित हैं। असल में हम पहले ही टेराहर्टज संचार का प्रदर्शन कर चुके हैं जो 6जी से जुड़ी हमारी प्रगति को दिखाता है।' प्रस्तुति में कहा गया कि सैमसंग की 6जी प्रौद्योगिकी की रफ्तार 5जी से 50 गुना ज्यादा है। कंपनी के श्वेत पत्र के मुताबिक सैमसंग को 6जी मानक और उसका व्यवसायीकरण कम से कम 2028 तक और व्यापक व्यवसायीकरण 2030 के आसपास पूरा होने की उम्मीद है।

क्या है कृष्णा और मोरपंख का संबंध

भगवान श्रीकृष्ण को मोर मुकुट धारी कहा जाता है क्योंकि वे अपने मुकुट पर मोर पंख धारण करते थे। मोरपंख धारण करने के पांच कारण बताए जाते हैं, लेकिन हमें तो मात्र एक कारण ही समझ में आता है। आओ जानते हैं मोर पंख धारण करने की कथा।

1. राधा की निशानी : महारास लीला के समय राधा ने उन्हें वैजयंती माला पहनायी थी। कहते हैं कि एक बार श्रीकृष्ण राधा के साथ नृत्य कर रहे थे तभी उनके साथ ही झूमकर नृत्य कर रहे एक मोर का पंख भूमि पर गिर गया तो प्रभु श्रीकृष्ण ने उठाकर उसे अपने सिर पर धारण कर लिया। जब राधाजी ने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि इन मोरों के नाचने में उन्हें राधाजी का प्रेम दिखता है। कहते हैं कि श्री राधा रानी के यहां बहुत सारे मोर थे। यह भी कहा जाता है कि बचपन से ही माता यशोदा अपने लल्ला के सर इस मोर पंख को सजाती थीं।वैजयंती माला के साथ ही मोर पंख धारण करने की एक बड़ी वजह राधा से उनका अटूट प्रेम है। मात्र इस एक बात के अलवा अन्य बातें सिर्फ मनमानी है।

2. जीवन के सभी रंग : मोरपंख में सभी रंग समहाहित है। भगवान श्रीकृष्ण का जीवन कभी एक जैसा नहीं रहा। उनके जीवन में सुख और दुख के अलावा कई अन्य तरह के भाव भी थे। मोरपंख में भी कई रंग होते हैं। यह जीवन रंगीन है लेकिन यदि आप दुखी मन से जीवन को देखेंगे तो हर रंग बेरंग लगेगा और प्रसन्न मन से देखेंगे तो यह दुनिया बहुत ही सुंदर है बिल्कुल मोरपंख की तरहा।

3. ग्रह दोष : कई ज्योतिष विद्वान मानते हैं कि भगवान श्रीकृष्ण ने यह मोरपंख इसलिए धारण किया था क्योंकि उनकी कुंडली में काल सर्प दोष था। मोर पंख धारण करने से यह दोष दूर हो जाता है, लेकिन जो जगत पालक है उसे किसी काल सर्प दोष का डर नहीं।

4. ब्रह्मचर्य का प्रतीक : कई लोग यह मानते हैं कि मोर ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। मोर पूरे जीवन एक ही मोरनी के संग रहती है। मोरनी का गर्भ धारण मोर के आंसुओ को पीकर होता है। अतः इसीलिए इतने पवित्र पक्षी के पंख को स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने मष्तक पर धारण करते हैं।

5. शत्रु और मित्र समान : कहते हैं कि भगवान श्रीकृष्ण मोर पंख धारण करके यह संदेश देना चाहते हैं कि मेरे लिए दोनों ही समान है। श्रीकृष्ण के भाई शेषनाग के अवतार थे और मोर तो नाग का शत्रु होता है। मोरपंख को माथे पर लगा कर उन्होंने यह बताया है कि मित्र और शत्रु के लिए उनके मन में समभाव है।

गणेशजी को ये 5 चीजें अर्पित करने से वे हो जाते हैं प्रसन्न

बुधवार का दिन चतुर्थी तिथि गणेशजी के खास समय है। इस दिन इनकी विशेष पूजा करना चाहिए। पूजा करने के दौरान गणेशजी को विशेष वस्तुएं अर्पित की जाती है जो कि उनके पसंद की होती है। इन वस्तुओं को अर्पित करने से गणपतिजी प्रसन्न हो जाते हैं। आओ जानते हैं कि वे 5 वस्तुएं कौनसी है।

1. मोदक के लड्डू : गणेशजी को मोदक या लड्डू का नैवेद्य अच्छा लगता है। मोदक भी कई तरह के बनते हैं। महाराष्ट्र में खासतौर पर गणेश पूजा के अवसर पर घर-घर में तरह-तरह के मोदक बनाए जाते हैं। मोदक के अलावा गणेशजी को मोतीचूर के लड्डू भी पसंद हैं। शुद्ध घी से बने बेसन के लड्डू भी पसंद हैं। इसके अलावा आप उन्हें बूंदी के लड्डू भी अर्पित कर सकते हैं। नारियल, तिल और सूजी के लड्डू भी उनको अर्पित किए जाते हैं। गणेशजी को घी और गुड़ का भोग भी लगाया जा सकता है।

2. दुर्वा : गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने की परंपरा है। गणेश जी को दूर्वा बहुत ही प्रिय है। दूर्वा के ऊपरी हिस्से पर तीन या पांच पत्तियां हों तो बहुत ही उत्तम है।

3. फूल : आचार भूषण ग्रंथ के अनुसार भगवान श्रीगणेश को तुलसीदल को छोड़कर

सभी प्रकार के फूल चढाएं जा सकते हैं। पद्मपुराण आचाररत्न में भी लिखा है कि 'न तुलस्या गणाधिपम'अर्थात् तुलसी से गणेश जी की पूजा कभी न करें। हालांकि अक्सर उन्हें गेंदे के फूल चढ़ाए जाते हैं।

4. केले : गणेशजी को केले बहुत पसंद है। उन्हें कभी भी एक केला ना अर्पित करें। जोड़े से केले चढ़ाएं।

5. सिंदूर करें अर्पित : गणेशजी को सिंदू भी अर्पित किया जाता है। सिंदूर मंगल का प्रतीक होता है। गणपति को सिन्दूर लेपन के विषय में शिवपुराण में एक श्लोक मिलता है। इसके मुताबिक 'आनने तव सिन्दूरं दृश्यते साम्प्रतं यदि। तस्मात् त्वं पूजनीयोअसि सिन्दूरेण सदा नरैः।।' अर्थात् जब भोलेनाथ ने जी गणेश जी का सिर काट दिया और हाथी का सिर लगाया तब उसमें पहले से ही सिंदूर का लेपन हो रहा था। मां पार्वती ने जी जब उस सिंदूर को देखा तो उन्होंने गणपति जी से कहा कि उनके मुख पर जिस सिन्दूर का विलेपन हो रहा है, मनुष्य उसी सिन्दूर से सदैव उनकी पूजा करेंगे। इस तरह से श्री विघ्नहर्ता को सिन्दूर का विलेपन किया जाता हैं।

इसके अलावा सुपारी, साबुत हल्दी, मौली का धागा और जनेऊ भी अर्पित की जाती है। जय गणेश।

लाल किताब में गुड़ खाने का क्यों बोला जाता है?

भारतीय परंपरा में गन्ना और गुड़ का बहुत प्रचलन है। यह सेहत के साथ ही ज्योतिष उपाय में भी उपयोग किया जाता है। गुड़ और घी को मिलाकर उपले पर उसकी धूप देने से गृहकलाह और ग्रहदोष समाप्त हो जाते हैं। आओ जानते हैं कि लाल किताब में गुड़ खाने का क्यों बोला जाता है।

1. लाल किताब के अनुसार गुड़ और गेहूं सूर्य ग्रह की कारक वस्तु है।

2. पत्रिका में यदि सूर्य कमजोर है तो गुड़ खाकर जल पीकर ही कोई कार्य प्रारंभ करें।

3. बहते पानी में गुड़ बहाने से भी सूर्य के दोष दूर होते हैं।

4. 800 ग्राम गेंहू व 800 ग्राम गुड़ रविवार से 8 दिन तक मंदिर में भेंट करें।

5. सूर्य द्वादश भाव में हो तो बंदरों को गुड़ खिलाएं।

6. देशी गुड़ घर में रखें और समय समय पर उसे थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे तो सूर्य बलवान होगा।

7. किसी भी प्रकार का भय हो तो तांबे के बर्तन में गुड़ रखकर हनुमानजी के मंदिर में दान दें और वहीं बैठकर धूप-दीप जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा कुछ मंगलवार और शनिवार को करें।

8. हनुमानजी को गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाने से उनकी कृपा बनी रहती है।

9. भोजन में गुड़ का प्रयोग करने से सेहत लाभ मिलता है और थोड़ा थोड़ा गुड़ खाते रहने से धन की आवक भी बढ़ती है।

10. मंगलवार को सवा किलो गुड़ जमीन में दबाने से भाई बहन में समझौता हो जाता है।

गोदन्ती रत्न पहनने के 5 फायदे

प्राचीन ग्रंथों में रत्नों के 84 से अधिक प्रकार बताए गए हैं। उनमें से बहुत तो अब मिलते ही नहीं। मुख्यतः 9 रत्नों का ही ज्यादा प्रचलन है। इन 9 रत्नों के ही उपरत्न भी बहुत से हैं। आओ जानते हैं गोदन्ती के बारे में 5 खास बातें। लहसुनिया किसे पहनना चाहिए और किसे नहीं, जानिए

1. गोदंती लहसुनिया का उपरत्न है। लहसुनिया को पहनने के जो फायदे है वहीं इसके पहने के भी फायदे हैं।
2. गोदंती के स्वामी ग्रह चंद्रमा हैं और उनकी राशि कर्क है। अतः इससे पहने से चंद्रदोष दूर होता है। इसे चंद्रकांता मणि भी कहते हैं।
3. इस रत्न को धारण करने से मानसिक तनाव भी कम होता है।
4. यह रतन भाग्य को जागृत करके सकारात्मक एनर्जी को बढ़ाता है और आपके आसपास प्रसन्नता निर्मित कर देता है।
5. करियर और व्यापार में भी यह रत्न पहनने से सफलता मिलती है।

घोर संकट से बचाए, लाल किताब के ये 10 उपाय

लाल किताब में परंपरागत और स्थानीय संस्कृति के अनुभवों पर आधारित उपाय बताए गए हैं। इसमें एक और जहां वास्तुशास्त्र की बात की गई है तो दूसरी ओर सामुद्रिक विज्ञान को बताया गया है। आओ जानते हैं कि ऐसे कौन से 10 उपाय हैं जिन्हें करने से घोर संकट से बचा जा सकता है।

1. प्रतिदिन हनुमान मंदिर जाएं और पीपल को जल चढाएं। हनुमान चालीसा पढ़ें। हनुमानजी को चोला चढ़ाएं। प्रतिदिन नहीं जा सकते हैं तो प्रति मंगल, गुरु और शनिवार को मंदिर जाएं। मंदिर के वृद्ध पुजारी या शिक्षक को पीला वस्त्र, धार्मिक पुस्तक या पीले खाद्य पदार्थ दान करें।

2. एकादशी, प्रदोष या गुरुवार का व्रत रखें। पीला वस्त्र धारण करें। प्रतिदिन केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। नाभि पर घी लगाएं। गुरुवार को नमक न खाएं। अपने या दूसरों के प्रति कटु वचन न बोलें। मुंह से गाली न निकालें। गृहकलह से बचें। मन में बुरे खयाल न लाएं। हमेशा सकारात्मक सोचें। इसके लिए घर में प्रतिदिन सुबह और शाम को कर्पूर जलाएं।

3. घर में 10 वस्तुएं अवश्य रखें। पहला चांदी से बना ठोस हाथी, दूसरा पत्थर की घट्टी, तीसरा पीतल-तांबे के बर्तन, चौथा मिट्टी के बर्तन में शहद, पांचवां काला सूरमा, छठा चांदी की डिब्बी जिसमें पानी भरा हो, सातवां काला सूरमा, आठवां देशी गुड़, नौवां चांदी का एक चौकोर टुकड़ा और दसवां हनुमानजी का चित्र या मूर्ति।

4. शनि के मंदे कार्य न करें, जैसे परस्त्रीगमन, शराब पीना, ब्याज का धंधा करना और किसी मनुष्य या प्राणी को सताना। प्रति शनिवार को छाया दान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 11 शनिवार को छाया दान करें।

5. वृक्ष, चींटी, पक्षी, गाय, कुत्ता, कौवा, कछुआ, मछली, वृद्ध, अनाथ, कन्या, अशक्त मानव आदि प्राणियों के अन्न-जल की व्यवस्था करने से इनकी हर तरह से दुआ मिलती है। अतः इन सभी को अन्न और जल देते रहने से पितृदोष, राहु-केतु दोष, शनि दोष, शुक्रदोष आदि दोष तो दूर होते ही हैं साथ ही व्यक्ति कर्ज, आकस्मिक संकट और दुर्घटना से भी बचा रहता है।

6. अलग-अलग पानीदार नारियल लेकर अपने और अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर से 21 बार वार कर उसे अग्नि में जला दें। इसी तरह 21 बार वार कर बहते पानी में बहा दें।

7. तांबे के लोटे में जल भरकर उसे सिरहाने रखकर सोएं और सुबह उठते ही उसे बाहर ढोल दें या कीकर के वृक्ष में डाल दें। काला और सफेद दोरंगी कंबल 21 बार खुद पर से वार कर किसी गरीब को दान करें।

8. बहते पानी में रेवड़ियां, बताशे, शहद या सिंदूर बहाएं। कभी-कभी आंखों में काला सूरमा लगाएं।

9. यदि आप संकटों से जूझ रहे हैं, बार-बार एक के बाद एक कोई न कोई संकट से आप घिर जाते हैं तो किसी की शवयात्रा में श्मशान से लौटते वक्त कुछ सिक्के पीछे फेंकते हुए आ जाएं।

10. घर के वास्तुदोष को मिटाने के लिए कर्पूर का बहुत? महत्व है। यदि सीढ़ियां, टॉयलेट या द्वार किसी गलत दिशा में निर्मित हो गए हैं तो सभी जगह 1-1 कर्पूर की बट्टी रख दें। वहां रखा कर्पूर चमत्कारिक रूप से वास्तुदोष को दूर कर देगा।

क्या है कोरोना का नया डेल्टा+ वैरिएंट

क्यों माना जा रहा इसे संभावित तीसरी लहर की वजह?

नई दिल्ली। एजेंसियां

देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार अभी थम ही रही है, इस बीच तीसरी लहर की संभावनाओं ने लोगों और सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। आने वाले हफ्तों या महीनों में भारत में कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना जताई गई हैं। इस बार सरकार की चिंताएं बढ़ाई हैं कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वैरिएंट ने। फिलहाल तो कोरोना वायरस का ये वैरिएंट(प्रकार या रूप) सिर्फ महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश में मिला है लेकिन इसके तेजी से फैलने की आशंका जताई गई है।

केंद्र सरकार ने अभी तक डेल्टा प्लस को वैरिएंट ऑफ इंटरेस्ट (Variant of Interest) की श्रेणी में रखा है। हालांकि, इस वायरस के एक बार फिर से तेजी से संक्रमण फैलाने का खतरा है। आइए जानते हैं आखिर कोरोना वायरस का नया डेल्टा प्लस वैरिएंट है क्या और इसे क्यों संभावित तीसरी लहर के पीछे का कारण माना जा रहा है।

क्या है डेल्टा प्लस वैरिएट?

देश में कोरोना का अब एक नया वैरिएंट सामने आया है जो पिछले डेल्टा वैरिएंट के काफी करीब है। इसे AY.1 या डेल्टा प्लस वैरिएंट नाम दिया गया है। यह डेल्टा वैरिएंट के म्यूटेशन से बना है। यह डेल्टा वैरिएंट का विकसित रूप है। डेल्टा वैरिएंट पहली बार भारत में ही पाया गया था। देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान वायरस की चपेट में आए ज़्यादातर लोग इसी वैरिएंट के शिकार हुए थे। कोरोना का डेल्टा वैरिएंट देश में दूसरी लहर के पीछे की वजह रहा था।

कितना खतरनाक ?

कोरोना के डेल्टा प्लस वैरिएंट को लेकर अभी ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। केंद्र सरकार के पास भी इसके बारे में अभी बहुत कुछ पता नहीं है। इसे लेकर अध्ययन हो रहे हैं। भारत में इसके संक्रमण को लेकर अभी भी अध्ययन किया जा रहा है लेकिन सरकार ने स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन के कारण इसके खतरनाक रूप धारण करने की आशंका जताई है। इस वैरिएंट की गंभीरता को देखते केंद्र ने उन तीन राज्यों को एडवाइजरी जारी कर जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है जहां इनके सबसे अधिक केस सामने आए हैं।

देश में अबतक कितने केस आए?

भारत में इसके 40 मामले मिले है। देश के चार राज्यों में डेल्टा प्लस वैरिएंट के मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में ये मामले सामने आए हैं। डेल्टा प्लस के भारत में जो मामले मिले हैं उनमें महाराष्ट्र के दो जिलों रत्नागिरी और जलगांव में 16 मामले आए हैं। बाकी तमिलनाडु. केरल और मध्य प्रदेश में मिले हैं। इसे देखते हुए सरकार ने महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु और केरल को तैयार रहने के निर्देश भी दिए हैं।

देश में कहां आया था पहला केस ?

देश में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वैरिएंट का पहला मामला मध्य प्रदेश के भोपाल में सामने आया था। यहां एक 65 साल की महिला में ये वैरिएंट सबसे पहले पाया गया था।

दुनिया के 9 देशों तक पहुचा डेल्टा प्लस वैरिएंट

डेल्टा प्लस वैरिएंट फिलहाल भारत समेत नौ देशों-अमेरिका, ब्रिटेन, स्विटजरलैंड, पुर्तगाल, जापान, पोलैंड, नेपाल, चीन और रूस में मिला है। वैसे अभी तक विश्व स्वास्थ्य संगठन या किसी अन्य देश ने भी डेल्टा प्लस को वैरिएंट ऑफ कंसर्न करार नहीं दिया है। लेकिन दुनिया के कई देशों में डेल्टा प्लस वैरिएंट के मामले अब सामने आने लगे हैं।

जीनोम सिक्वेंसिंग से हुई पहचान

कोरोना के वैरिएंट की पहचान के लिए सरकार ने 10 प्रयोगशालाओं का एक कंसोर्टियम बनाया था। मई में इसमें 18 और प्रयोगशालाओं को जोड़ा गया। इन लेबोरेटरी में अब तक 45 हजार सैंपल की जीनोम सिक्वेंसिंग की गई है। डेल्टा प्लस वैरिएंट की पहचान भी इसी जीनोम सिक्वेंसिंग के माध्यम से हुई।

केंद्र सरकार डेल्टा प्लस वैरिएंट के प्रसार को रोकने के लिए उसके मामलों की बारीकी से निगरानी कर रही है। सरकार के मुताबिक, अगर कोरोना को लेकर लोग उचित व्यवहार करें तो वायरस के प्रसार में कमी आ सकती है।सरकारी ओर से कहा गया है कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकना हमारे हाथों में है। अगर हम अनुशासित रहते हैं, कोरोना से बचाव के नियमों का उचित तरीके से पालन करते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा दी जाती है तो तीसरी लहर को आने से रोका जा सकता है।

इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने दो अलग-अलग कोरोना वैक्सीन की डोज ली

रोम। एजेंसी

इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी ने दो अलग-अलग कोरोना वैक्सीन की डोज ली है। उन्होंने पहली डोज एस्ट्राजेनेका की ली थी। वहीं दूसरी डोज फाइजर की ली। यही नहीं जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने भी दो अलग-अलग वैक्सीन की डोज ली है। कोरिएरे डेला सेरा अखबार ने जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के टीकाकरण पर अपनी रिपोर्ट में इटली के प्रधानमंत्री को दी गई वैक्सीन की दूसरी डोज के बारे में बताया।

दोनों यूरोपीय नेताओं ने पहली खुराक यूके-स्वीडिश कंपनी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की ली थी। पिछले हफ्ते मारियो द्राघी ने कोरोना टीकों के संयुक्त उपयोग का समर्थन किया था। द्राघी के अनुसार वैक्सीन की पहली डोज लगने के बाद उनमें कम संख्या में एंटीबॉडी विकसित हुई। इसलिए उन्हें दूसरी डोज के लिए दूसरे टीके का उपयोग करने की सलाह दी गई। कोरिएरे के मुताबिक, सोमवार को ड्रैगी को फाइजर का टीका लगवाया। वहीं मर्केल को मॉडर्ना वैक्सीन लगाया गया।

इटली में कोरोना के मामलों और अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में भारी गिरावट आई है। ऐसे में अब यहां खुले में मास्क पहनने की अनिवार्यता नहीं रहेगी। सरकार ने जानकारी दी है कि कोरोना मामलों और अस्पताल में भर्ती होने में गिरावट आई है, ऐसे में 28 जून से खुले में मास्क पहनने की अनिवार्यता खत्म कर दी जाएगी।

पिछले साल अक्टूबर में जब देश महामारी की दूसरी लहर के दौरान बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए अधिकारी संघर्ष कर रहे थे, तो मास्क पहनना अनिवार्य किया गया था। मारियो द्राघी की सरकार अप्रैल से लगातार कोरोना से संबंधित प्रतिबंध हटा रही है। रेस्तरां, बार, सिनेमा और जिम हॉल पहले ही खोल दिए गए हैं। देशभर में आवाजाही को लेकर पाबंदियां भी हटा दी गई हैं। अब खुली जगहों पर लोगों को मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं होगी। लोगों को फिलहाल बंद सार्वजनिक क्षेत्रों में मास्क लगाना आवश्यक होगा। यह निर्णय अगले सोमवार से प्रभावी होगा।

रफ्तार पकड़ रहा 'कोरोना वैक्सीनेशन', टीका लगवाने वालों को नामी ब्रांड्स भी दे रहे तमाम 'ऑफर'

नई दिल्ली। कोरोना के खिलाफ चल रहे वैक्सीनेशन अभियान में 21 जून यानी 'योग डे' को नया रिकॉर्ड बना यानी एक दिन में देश में करीब 85 लाख से ज्यादा डोज दिए गए, इससे पहले, कोविड रोधी टीके की सर्वाधिक 48 लाख से अधिक डोज एक अप्रैल को लगाई गई थीं यानी नया रिकॉर्ड पुराने से करीब करीब दोगुने से थोड़ा कम है। वहीं देश के राज्यों की बात करें तो मध्यप्रदेश ने इसमें बाजी मारी और 21 जून को कोरोना महामारी के खिलाफ टीकाकरण महाअभियान के तहत सारे राज्यों में सबसे ज्यादा एक दिन में रिकार्ड 16.73 लाख लोगों को टीका लगाया गया। गौर हो कि 21 जून से देश में नई टीकाकरण नीति लागू हो गई है अब से वैक्सीनेशन की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और केंद्र राज्यों को 18 से ऊपर के सभी नागरिकों को टीका लगाने के लिए मुफ्त वैक्सीन देगा।

गौर हो कि भारत ने जनवरी में जब कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान शुरू किया था तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि टीका लगवाना न सिर्फ उन्हें घातक बीमारी से बचाने में कारगर होगा बल्कि पसंदीदा खाना खरीदने में छूट दिलाने, किराने का सामान खरीदने में अतिरिक्त बचत या फिर बैंक में जमा रकम पर ज्यादा ब्याज तक दिलाने में सहायक हो सकता है लेकिन अब ऐसा ही हो रहा है।

कोरोनाः मास्क से छूट देने वाले पहले देश इस्राइल पर टूटा महामारी का कहर, वैक्सीन ले चुके लोग हो रहे संक्रमित

एजेंसी। दुनिया भर में पिछले डेढ़ साल से कोरोना वायरस ने तबाही मचा रखी है। कई देशों में वायरस की दूसरी और तीसरी लहर ने भी जमकर कोहराम मचाया। पिछले हफ्ते ही इस्राइल ने आउटडोर और इनडोर मास्क से छूट देने वाला पहला देश होने का दावा किया था। इसके एक हफ्ते बाद कोरोना वायरस ने एक बार फिर इस्राइल पर अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कोरोना का डेल्टा वैरिएंट वैक्सीन ले चुके लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है।

इस्राइल उन देशों में शामिल हैं, जो अपनी आधी से अधिक आबादी का वैक्सीनेशन कर चुके हैं। इसके बाद इस्राइल ने तमाम पाबंदियां हटाने के साथ ही मास्क लगाने से छूट दे दी। इसके एक हफ्ते बाद ही इस्राइल में कोरोना संक्रमण के मामलों में अचानक से वृद्धि देखने को मिल रही है। कोरोना वायरस का खतरनाक डेल्टा वैरिएंट वैक्सीन ले चुके लोगों को भी तेजी से अपनी गिरफ्त में ले रहा है। इसके बाद वहां किशोरों को जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगाने की मांग की जा रही है।

अप्रैल के बाद पहली बार मिले 125 नए केस

इस्राइल में सोमवार को 125 नए कोरोना मरीज मिले। आधे से आबादी का टीकाकरण होने वाले देश में अप्रैल के बाद से एक दिन में मिलने नए कोरोना मरीजों की यह संख्या सबसे अधिक है। इस्राइल में जनवरी माह में कोरोना वायरस का प्रकोप चरम पर था। उस वक्त इस्राइल में प्रतिदिन 10 हजार मामले दर्ज किए जा रहे थे। लेकिन उसके बाद उस वक्त की नेतन्याहू सरकार ने तेजी से टीकाकरण कर वायरस पर काबू पा लिया था।

टीकाकरण करा चुके नौ शिक्षक निकले संक्रमित

कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए लागू सभी पाबंदियों को हटाए जाने के बाद रैंडम जांच करने के दौरान कई स्कूलों में संक्रमित मामले मिले। इस्राइली समाचार पत्र हारेट्ज के मुताबिक, इस्राइल के दो स्कूलों में जांच के दौरान वैक्सीन की पूरी डोज लगवा चुके नौ शिक्षक कोरोना संक्रमित मिले।

इस्राइल के नव निर्वाचित प्रधानमंत्री नफ्टाली बेनेट ने कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए नए प्रकोप की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि देश को एक बार फिर अपनी चपेट में लेना वाला डेल्टा वैरिएंट विदेश से लौट रहे यात्रियों की वजह से आया है। इसलिए अब अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सख्ती से जांच की जाएगी। इसी के साथ उन्होंने अपने नागरिकों से फिलहाल विदेश की यात्राएं कम से कम करने की सलाह दी है।बता दें कि इस्राइल में अब तक 840,079 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 6,428 लोगों की वायरस से जान जा चुकी है।

इंदौर से निकलेगी सस्ते वैंटिलेटर और आक्सीजन कन्सेंटेटर बनाने की राह

पोलोग्राउंड औद्योगिक क्षेत्र में बन रहे सस्ते और अधिक भरोसेमंद वेंटिलेटर

आक्सीजन कन्सेंटेटर मशीनों को बनाया बहु उपयोगी, रोक सकती है ब्लैक फंगस भी

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

कोविड-19 की महामारी के दौर में चिकित्सकीय सुविधाओं की कमी से पुरा देश परेशान हुआ है। महामारी के दौर में आक्सीजन की कमी और अस्पतालों में आईसीयू और वैंटीलेटरों का अभाव भी कई मरीजों की जान गई थी। वही कोरोना से पीडित मरीजों को संक्रमण बढने पर आक्सीजन देने की स्थिती बनी। ऐसे में आक्सीजन की सीमित सप्लाई से पुरा देश जुझता रहा था। इस कठिन दौर में भी जब आक्सीजन कन्सेंटेटर मशीनों की कमी और ऊंचे दाम से यह आम नागरिक की पंहुच से दूर थी। इंदौर के पोलोग्राउंड औद्योगिक क्षेत्र के एक कारखाने में आक्सीजन कन्सेंटेटर मशीन और वैंटीलेटर बनाने के लिए दिन रात मेहनत की जा रही थी। महामारी के कठिन दौर में दिन रात के प्रयासों के बाद बाजार में उपलब्ध आक्सीजन कन्सेंटेटर मशीन और वैंटीलेटर से बेहतर मशीनों को बनाने में सफलता मिल गई। इन उपकरणों को केंद्रीय स्वास्थ एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन टेस्ट करवाने और पंजीयन प्राप्त करने के बाद अब व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ किया जा रहा है। यूरोपियन स्टैंडर्ड के अनुरूप ट्रांसपेरेंट कवर वाले ये वैंटीलेटर वजन में कम, कीमत में सस्ते और उपयोग में आसान है। इनका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे छोटे क्लीनिक, एम्बुलेंस, और आवश्कता होने पर मोटरसायकल एम्बुलेंस में भी किया जा सकता है।

दिन रात लगे रहे तब मिली सफलता

पोलोग्राउंड औद्योगिक क्षेत्र में एसपी इंटप्राइजेस पहले भी नई तकनीकी को खोजने और उसे बनाने

में कार्यरत रहा है। इसके पहले सोलर एयर कंडीशनर पर काम कर चुके है। कोविड संक्रमण के दौर में जब लॉडडाउन से सब अपने घरों में थे तब श्री संजय पटवर्धन और उनके सहयोगियों सुबह से लेकर देर रात तक अपने कारखाने में आक्सीजन कन्सेंटेटर मशीन और वैंटीलेटर बनाने में जुटे थे। कई दिनों के लगातार प्रयासों के बाद अतंतः सफलता मिल गई। उन्होनें अपनी मशीनों के मॉडल तैयार पर उन्हें केंद्रीय स्वास्थ एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नियमों के अनुसार प्रयोगिक उपयोग, परीक्षण और प्रमाणन को सफलता पूर्वक प्राप्त किया है। उनकी बनाई आक्सीजन कन्सेंटेटर मशीन और वैंटीलेटर कई स्तर की जांच के बाद अब बाजार में उतरने को तैयार है।

वैंटीलेटर ऐसा जो घर में भी उपयोगी

श्री संजट पटवर्धन ने बताया कि वर्तमान में जारी कोविड संक्रमण के बाद अस्पतालों के साथ अब घरों में आईसीयू बनाए जाने लगे है। बाजार में मिलने वाले वैंटीलेटर के संचालन के लिए टैक्नीशियन की आवश्यकता होती है क्योकि मशीनें, इलेक्ट्रनिक न्यूमेटिक है और उन्हें मैनेंटेन करना जरूरी होता है। इनके सेफ्टी फीचर भी इंडियन कंडिशन के अनुसार कम है। वही आक्सीजन सेंसर, न्यूमेटिक फेल होने पर पता भी नही चलता है। इस स्थिती में मरीज की जान को भी खतरा होता है। वही उनकी बनाई मशीनों की जानकारी देते हुए उन्होनें बताया कि हमने वेंटीलेटर के 3 मॉडल बनाऐ है। इनमें से बेसिक मॉडल ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से उपयोग किया जा सकता है। इस मॉडल में आक्सीजन फ्लो वाटर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम से है जो कि किसी को भी आसानी से समझ में आ सकता है। वही पानी बदलने की समस्या को भी साधारण रखा गया है। जोकि ब्लैक फंगस जैसी बीमारियों का कारण है। उन्होनें बताया कि इन मशीनों में न्यूमोथोरेक्स आक्सीजन प्रेशर कंट्रोल दिया गया है।

यूरोपियन मानकों का किया पालन

श्री पटवर्धन ने बताया कि उनके बनाऐ हुए वेंटिलेटरों को यूरोपियन स्टैंडर्ड के अनुसार ट्रांसपेरेंट कवर में बनाया गया है। इससे मरीज के अटैंडर को मशीन में चल रही गतिविधियों को देखना आसान होता है। वही इमरजेंसी के लिए पावर बैकअप भी दिया गया है। जो कि सप्लाई बाधित होने की स्थिती में 4 घंटे तक चला सकती है। श्री पटवर्धन ने बताया कि इन वेंटीलेटर में आक्सीजन खत्म होने पर भी सप्लाइ मिलती रहे इसके लिए भी सिस्टम दिया गया है। जोकि अन्य वेंटिलेटरों में नही होता है।

4 मॉडल वेंटिलेटर के

श्री पटवर्धन ने बताया कि वेंटिलेटर के 4 मॉडल बनाऐ गए है। इन सभी मशीनों का परीक्षण और पंजीयन स्वास्थ विभाग की योजना में होने के बाद अब व्यवसायिक उत्पादन प्रारंभ किया गया है। इन्हें शेल्काजेन के नाम से तैयार किया जा रहा है। सबसे बडे मॉडल का वजन 25 किलों और कीमत 5 लाख और छोटा 52 हजार का है। इनकी कीमतें बाजार में उपलब्ध वेंटिलेटरों से लगभग 50 प्रतिशत कम है। उन्होनें बताया कि हाई फ्लो और लो फ्लों के आधार मेडिकल कंडीशन में टेस्ट करने के बाद इन्हे सप्लाय करना प्रारंभ किया है। लगभग 50 मशीनें बन कर भी तैयार है। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों से आए है।

आक्सीजन कन्सेंटेटर मशीन सस्ती और मजबूत

श्री पटवर्धन ने बताया कि चाइन से आने वाले आक्सीजन कन्सेंटेटर मशीनों में 5 लीटर आक्सीजन क्षमता लिखी होने पर लगभग 3 लीटर आक्सीजन मिलती है। जबकि हमारे द्वारा बनाऐ गए आक्सीजन कन्सेंटेटर मशीन पुर्णत भारतीय है और मानक के अनुसार है। इन्हें मेडिकल कंडीशन के अनुसार स्टेनलेस स्टील और पावडर कोटिंग बॉडी में बनाया है। इसमें 5 लीटर क्षमता की आक्सीजन कन्सेंटेटर मशीन 65 हजार में और 10 लीटर क्षमता का 1 लाख कीमत में उपलब्ध है। उन्होनें बताया कि हमारी मशीनों में आक्सीजन सप्लाय, प्योरिटी और सर्विस की दिक्कत नही आएगी। जबकि चायना की मशीनो में यह तीनों ही नही है। श्री पटवर्धन का मानना है कि उनके बनाऐ आक्सीजन कन्सेंटेटर मशीन भारत सरकार के मानकों को पुरा करते है।

सालों का अनुभव देश के लिए

बीते 25 वर्षों से इंग्लैंड में रह रहे डॉक्टर एसके भंडारी और उनकी पत्नी डॉक्टर पुर्णिमा भंडारी ने वहां रहते हुए वेंटिलेटर और आक्सीजन कन्सेंटेटर पर रिसर्च की। इस दौरान उन्होनें बाजार में उपलब्ध उपकरणों की कमियों और तकनीकी खामियों को समझा

और उन्हें सुधारने के लिए नई टैक्नोलॉजी पर खोज की। इसके बाद उन्होनें खुद की डिजाईन और तकनीक से वेंटीलेटर के निर्माण किया। इसके बाद उन्होनें यूनाईटेड स्टेट आफ अमेरिका और भारत के लिए इसके पेटेंट के लिए भी आवेदन किया। इन सब के बाद भारत लौटने पर उन्होने अपने गृह नगर इंदौर में इनके निर्माण के लिए टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में पोलोग्राउंड स्थित एसपी इंटरप्राइजेस के संचालक और उद्योगपति इंजिनियर श्री संजय पटर्वधन से अनुबंध किया। उन्होनें अपनी वैंटीलेटर की तकनीक को अधिकृत रूप से श्री पटवर्धन को दे दिया है।

हैवी फिल्टर, नही होगा ब्लैक फंगस का डर

श्री पटवर्धन ने बताया कि उनके आक्सीजन कन्सेंटेटर मशीन में बारिश के दिनों में हीम्युडिटी और गर्मी के दिनों में ड्रायनेस से होने वाले आक्सीजन सप्लाय और गुणवत्ता पर पुरी तरह नियंत्रण किया गया है। इसमें लगे फिल्टर को आसानी से साफ किया जा सकता है। साथ ही आक्सीजन टैंक भी लगाया गया है जो कि इमरजेंसी में काम आता है। इसमें लगे मीटर आक्सीजन की प्युरिटी की जानकारी देते रहते

है। साथ ही कुलिंग के लिए कॉपर क्वाइल का उपयोग किया गया है। उन्होनें बताया कि चाईना की मशीनों में इसकी जानकारी देने का कोई सिस्टम नही है। श्री पटवर्धन ने बताया कि भारतीय मानकों के अनुसार आक्सीजन कन्सेंटेटर मशीन को 90 प्रतिशत और डब्लूएचओ के अनुसार 82 प्रतिशत आक्सीजन कन्सेंटेटर को देना चाहिए। उनके बनाऐ आक्सीजन कन्सेंटेटर मशीन में बैक्टिरीया फिल्टर भी लगाया है। जो कि ब्लैक फंगस जैसी बीमारियों से बचाव के लिए जरूरी है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।